केन्द्रीय आयोजना 2013-2014 की विशेषताएं
Highlights of Central Plan 2013-2014

(₹ करोड़)

ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- 33000 वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों, जिसमें प्रौढ़ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को राजी हों को 100 दिवस की रोजगार कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु।

आजीविका

- 4000 अ.जा./अ.ज.जा., महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग लोगों सहित समाज के संवेदनशील तबकों, गरीब परिवारों को लाभप्रद स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों की पहुंच से सशक्त बनाकर उनकी गरीबी दूर करने हेतु।

ग्रामीण आवास

- 15184 इन्दिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को मकानों के निर्माण तथा कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए। घरों के निर्माण के लिए कुल आवंटन का 60% अ.जा./अनु.ज.जा. के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- 21700 अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए पात्र कनेक्ट न हुए ग्रामीण निवासियों हेतु कनेक्टिविटी की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु। मौजूदा ग्रामीण सड़कों का व्यवस्थित स्तरोन्नयन भी इस स्कीम का अनिवार्य भाग है।

पेयजल आपूर्ति

- 11000 सभी ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु।
- 4260 ग्रामीण स्वच्छता हेतु।

भूमि संसाधन

- 5387 एकीकृत जल संभरण प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु।

कृषि तथा सहकारिता

- 9954 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य आयोजना) हेतु।
- 2250 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु।
- 1693 राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन हेतु।
- 1600 राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु।
- 1200 राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम हेतु।
- 700 मौसम आधारित फसल बीमा हेतु।
- 550 राज्यों को विस्तार सेवाओं की सहायता हेतु।
- 550 पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन हेतु।
- 500 समेकित तिलहन, पॉम आयल, दलहन तथा मक्का विकास हेतु।

पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी

- 459 पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण।
- 300 डेयरी उद्यमिता विकास हेतु।
- 138 राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

- 520 अग्रवी प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि विस्तार कार्यक्रमों हेतु।
- 475 कृषि शिक्षा हेतु।
- 465 फसल विज्ञान में शोध मामलों का निवारण।
- 400 विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

- 200 सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु।
- 145 भाण्डागार क्षमताओं के निर्माण हेतु।

पर्यावरण तथा वन

- 1198 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण और राष्ट्रीय नदी संरक्षण हेतु।

(₹ in Crore)

RURAL DEVELOPMENT

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

- 33000 for providing a legal guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

Aajeevika

- 4000 for reducing poverty by enabling the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities including coverage of vulnerable sections of the society including SCs/STs, women, minorities and persons with disabilities.

Rural Housing

- 15184 for providing assistance to rural BPL households for construction of houses and upgradation of kutcha houses under Indira Awaas Yojana. 60% of the total allocation is for construction of houses for BPL families of SCs/STs.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

- 21700 for providing connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads. The systematic upgradation of existing rural roads is also an essential component of the scheme.

DRINKING WATER SUPPLY

- 11000 for supplementing the States in their effort to provide safe and adequate drinking water to all rural habitations.
- 4260 for rural sanitation.

LAND RESOURCES

- 5387 for Integrated Watershed Management Programme.

AGRICULTURE AND COOPERATION

- 9954 for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (State Plan).
- 2250 for National Food Security Mission.
- 1693 for National Mission on Micro Irrigation.
- 1600 for National Horticulture Mission.
- 1200 for National Agriculture Insurance Scheme.
- 700 for Weather Based Crop Insurance.
- 550 for support to States' Extension Services.
- 550 for Horticulture Mission for North East and Himalayan States.
- 500 for Integrated Oilseeds, Oil Palm, Pulses and Maize Development.

ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

- 459 for Livestock Health and Disease Control.
- 300 for Dairy Entrepreneurship Development.
- 138 for National Fisheries Development Board.

AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

- 520 for Agricultural Extension programmes to disseminate frontline technologies.
- 475 for Agricultural Education.
- 465 for addressing the research issues in Crops Science.
- 400 for World Bank Aided National Agricultural Innovation Project.

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

- 200 for computerization of Public Distribution System operations.
- 145 for construction of warehousing capacity.

ENVIRONMENT AND FORESTS

- 1198 for Ecology and Environment and National River Conservation.

- 1041 वानिकी तथा वन्य जीव एवं राष्ट्रीय वृक्षारोपण तथा पारिस्थितिकी विकास हेतु।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

- 1418 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु।

उपभोक्ता मामले

- 132 उपभोक्ता जागरुकता एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु।

स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता

- 27258 सर्वशिक्षा अभियान हेतु।
- 13215 स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु।
- 3983 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु।

उच्च शिक्षा

- 7299 तकनीकी शिक्षा हेतु।
- 5769 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु।
- 400 आईसीटी के जरिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन।

महिला तथा बाल विकास

- 17700 एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु।
- 650 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना हेतु।
- 500 इन्दिरा गांधी मैत्रीत्व सहयोग योजना हेतु।
- 300 एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु।
- 300 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन हेतु।

सूचना प्रौद्योगिकी

- 830 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अवसंरचना सुधार हेतु।
- 700 ई-गर्वनेंस कार्य्रक्रम हेतु।
- 360 सम्पूर्ण देश में ज्ञान प्रदायक संस्थाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना हेतु।
- 205 अनुसंधान और विकास के लिए उन्नत अभिकरण विकास केन्द्र हेतु।

दूरसंचार

- 3000 सार्वभौम सेवा दायित्व के अन्तर्गत योजनाओं हेतु।
- 2425 रक्षा सेवाओं हेतु आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क हेतु।

स्वास्थ्य

- 20999 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु।
- 8166 स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु।

आयुष

- 177 आयुष प्रणाली के विकास हेतु।
- 100 होम्योपैथी प्रणाली के विकास हेतु।
- 86 यूनानी प्रणाली के विकास हेतु।
- 59 योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा के विकास हेतु।

सूचना तथा प्रसारण

- 544 प्रसारण क्षेत्र हेतु।
- 235 सूचना क्षेत्र हेतु।
- 126 फिल्म क्षेत्र हेतु।

शहरी विकास

- 1156 मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए।
- 1132 मेट्रो रेल परियोजनाओं के अनुषंगी ऋण हेतु।
- 402 सामान्य पूल रिहायशी आवास हेतु।
- 125 सामान्य पूल कार्यालय स्थल हेतु।

राजमार्ग

- 14000 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों हेतु।
- 11627 टोल प्रेषण सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश हेतु।
- 5422 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय हेतु।
- 3300 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

विद्युत

- 4500 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए। 3300 अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा लगभग 20 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

- 1041 for Forestry and Wild Life and National Afforestation and Eco-Development.

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

- 1418 for Prime Minister's Employment Generation Programme.

CONSUMER AFFAIRS

- 132 for Consumer Awareness and Consumer Protection.

SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

- 27258 for Sarva Shiksha Abhiyan
- 13215 for National Programme of Mid Day Meals in Schools.
- 3983 for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

HIGHER EDUCATION

- 7299 for Technical Education.
- 5769 for University Grants Commission.
- 400 for National Mission for Education through ICT.

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

- 17700 for Integrated Child Development Services.
- 650 for Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls.
- 500 for Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana.
- 300 for Integrated Child Protection Scheme.
- 300 for National Nutrition Mission.

INFORMATION TECHNOLOGY

- 830 for National Informatics Centre to improve infrastructure.
- 700 for e-Governance programme.
- 360 for establishing National Knowledge Network to connect Knowledge Institutions across the country.
- 205 for Centre for Development of Advanced Computing for undertaking R&D.

TELECOMMUNICATIONS

- 3000 for schemes under Universal Services Obligation.
- 2425 for OFC based Network for Defence Services.

HEALTH

- 20999 for National Health Mission.
- 8166 for Health Sector.

AYUSH

- 177 for development of Ayurveda system.
- 100 for development of Homoeopathy system.
- 86 for development of Unani system.
- 59 for development of Yoga and Naturopathy system.

INFORMATION AND BROADCASTING

- 544 for broadcasting sector.
- 235 for information sector.
- 126 for film sector.

URBAN DEVELOPMENT

- 1156 for equity investment in Metro Rail Projects.
- 1132 for subordinate debt to Metro Rail Projects.
- 402 for General Pool Residential Accommodation.
- 125 for General Pool Office Accommodation.

HIGHWAYS

- 14000 Internal and Extra Budgetary Resources for National Highways Authority of India.
- 11627 Investment of National Highways Authority of India including Remittance of Toll.
- 5422 Capital Outlay on National Highways.
- 3300 Special Accelerated Road Development Programme for North East Region.

POWER

- 4500 for Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana to achieve electrification of 3300 un-electrified villages and offering electricity connections to around 20 lakh BPL households.

- 575 पुनर्संरचित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम हेतु। इसका उद्देश्य राज्य विद्युत इकाइयों को एटी एण्ड सी हानि को घटाकर 15% के स्तर तक लाने की सुविधा प्रदान करना है।

कपड़ा

- 2400 प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु निधि स्कीम।
- 300 एकीकृत कपड़ा पार्कों हेतु।
- 291 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- 1500 अनुसूचित जातिओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु। (लगभग 55 लाख विद्यार्थी)।
- 1051 अनुसूचित जाति उप-आयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता हेतु। (लगभग 10.51 लाख एससी लाभार्थी)।
- 900 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु। (लगभग 25 लाख ओबीसी लाभार्थी)।

जनजातीय कार्य

- 750 अ.ज.जा. विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन हेतु।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

- 60 पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋणों हेतु।
- 45 पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम हेतु।

अल्पसंख्यक मामले

- 1250 अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रमों हेतु।
- 950 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति हेतु।
- 550 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति हेतु।
- 270 व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 534 विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड हेतु।
- 345 संबंध और आर एंड डी मिशन हेतु।
- 225 विज्ञान और अभियांत्रिकी (अनुसंधान और विकास सहायता बोर्ड) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में बहु-विद्या अनुसंधान हेतु।
- 200 राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु।

अंतरिक्ष

- 350 पीएसएलवी-सी परियोजना हेतु।
- 305 जीएसएटी-16 उपग्रह-प्रक्षेपण श्रृंखला हेतु।
- 300 जीएसएटी-15 उपग्रह-प्रक्षेपण श्रृंखला हेतु।
- 270 इन्सेट-3डी प्रक्षेपण श्रृंखला हेतु।
- 216 जीएसएलवी-परिचालन (एमके-III परिचालन सहित) हेतु।
- 203 उन्नत संचार उपग्रह (जीसेट-11 प्रक्षेपण सेवा सहित) हेतु।
- 168 मंगल कक्षा मिशन हेतु।

नागर विमानन

- 5000 नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लि. में इक्विटी प्रदान करने हेतु।

परमाणु ऊर्जा

- 3739 अनुसंधान और विकास हेतु।
- 1240 उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।
- 475 अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूकिलयर एक्सपेरीमेन्टल रीएक्टर हेतु।
- 301 पंजाब/चंडीगढ़ में प्रस्तावित नई कैंसर संस्था सहित टाटा मेमोरियल सेंटर को सहायता अनुदान हेतु।
- 185 खनिज क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।

नाभिकीय विद्युत

- 251 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश हेतु।

पृथ्वी विज्ञान

- 200 पोलर साईंस और क्रायोस्फीयर कार्यकलापों के लिए अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु।
- 200 वायुमंडलीय वेध प्रणाली नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु।

खेल

- 200 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान की योजना हेतु।

- 575 for Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme to facilitate State Power Utilities to reduce the level of AT&C loss to 15%.

TEXTILES

- 2400 for Technology Upgradation Fund Scheme.
- 300 for Integrated Textile Parks.
- 291 for Catalytic Development Programme.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

- 1500 for Post-Matric scholarship for Scheduled Castes (about 55 lakh students).
- 1051 for Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (about 10.51 lakh SC beneficiaries).
- 900 for Post-Matric scholarship for Other Backward Classes (about 25 lakh OBC beneficiaries).

TRIBAL AFFAIRS

- 750 for Post-Matric scholarships for Scheduled Tribe students and upgradation of merit of Scheduled Tribe students.

DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- 60 for loans to North Eastern Development Finance Corporation.
- 45 for North Eastern States Road Investment Programme.

MINORITY AFFAIRS

- 1250 for Multi-Sectoral Development Programmes for Minorities.
- 950 for Pre-Matric scholarship for Minorities.
- 550 for Post-Matric scholarship for Minorities.
- 270 Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 534 for Science & Engineering Research Board.
- 345 for Alliance and R&D Mission.
- 225 for multi-disciplinary research in frontier areas of Science & Technology (Research and Development Support).
- 200 for National Geographic Information System.

SPACE

- 350 for PSLV-C Project.
- 305 for GSAT-16 Satellite - Launch Series.
- 300 for GSAT-15 Satellite - Launch Series.
- 270 for INSAT-3D Launch Series.
- 216 for GSLV - Operational (including Mk-III Operational).
- 203 for Advanced Communication Satellite (GSAT-11 including Launch Services).
- 168 for Mars Orbiter Mission.

CIVIL AVIATION

- 5000 for equity infusion in National Aviation Company of India Limited.

ATOMIC ENERGY

- 3739 for Research and Development.
- 1240 for Industries Sector Projects.
- 475 for International Thermonuclear Experimental Reactor.
- 301 for Grants-in-Aid to Tata Memorial Centre including new cancer institutions proposed in Punjab/Chandigarh.
- 185 for Minerals Sector Projects.

NUCLEAR POWER

- 251 for investment in Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd.

EARTH SCIENCES

- 200 for strengthening research facilities for the Polar Sciences and Cryosphere activities.
- 200 for operation and maintenance of Atmospheric Observation Systems Network.

SPORTS

- 200 for the scheme of Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan.

संस्कृति

- 242 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेतु।
- 156 नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय हेतु।

रसायन और पेट्रो रसायन

- 1000 लापेटकाता, असम में पेट्रोरसायन गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करने हेतु।

भेषज

- 113 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली और नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए।

पंचायती राज

- 455 राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान हेतु।

उद्योग

- 342 राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना।

डाक

- 532 आईटी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण हेतु।

वित्त

- 14000 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण हेतु।
- 700 नाबार्ड की पूंजी बढ़ाने के लिए।
- 700 एक्जिम बैंक को उसकी प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता।
- 400 आईआईएफसीएल को उसकी प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता।
- 100 देश के पिछड़े क्षेत्रों में महिला स्वयं सेवा समूहों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ महिला स्वयं सेवा समूह विकास निधि के सृजन हेतु।
- 100 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ स्थापित भारतीय सूक्ष्म वित साम्यता कोष के लिए।

(वास्तविक लक्ष्य)

उर्वरक

- 129.99 लाख मी. टन लक्षित नाइट्रो जनित उर्वरक उत्पादन।
- 47.89 लाख मी. टन लक्षित फास्फोरसयुक्त उर्वरक उत्पादन।

कोयला और लिग्नाइट

- 609.55 मि.टन वर्ष 2013-14 के दौरान कोयले की घरेलू उपलब्धता आंकी गई है, जो कोल इंडिया लि. और अन्य से पूरा करने का अनुमान है।
- 26.03 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान।

इस्पात

- 26.00 मिलियन टन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
- 17.41 मिलियन टन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

- 3000 मेगावाट पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर शक्ति से ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए।
- 1.00 लाख पारिवारिक किस्म के बायोगैस संयंत्रों का विनिर्माण।

रेलवे

- 3000 किलोमीटर ट्रैक का नवीकरण।
- 1300 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण।
- 750 किलोमीटर डबल लाइन करने का और अतिरिक्त 675 रेल इंजनों के विनिर्माण का लक्ष्य।
- 500 किलोमीटर नई लाइनें।
- 450 किलोमीटर का गेज परिवर्तन।

CULTURE

- 242 for Archaeological Survey of India.
- 156 for Nehru Memorial Museum and Library.

CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

- 1000 for establishment of a Petrochemical Gas Cracker Project at Lepetkata, Assam.

PHARMACEUTICALS

- 113 for National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali and establishment of new NIPERs.

PANCHAYATI RAJ

- 455 for Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan.

INDUSTRY

- 342 for National Automotive Testing and Research & Development Infrastructure Project.

POSTS

- 532 for IT induction and modernisation.

FINANCE

- 14000 for recapitalisation of Public Sector Banks to help them maintain comfortable level of CRAR in compliance with Basel III norms.
- 700 for augmenting the capital of NABARD.
- 700 for equity support to EXIM Bank to increase its paid up capital.
- 400 for equity support to IIFCL to increase its paid up capital.
- 100 for creating Women's Self Help Groups (SHG) Development Fund with NABARD to promote Women's SHG in backward areas of the country.
- 100 for India Microfinance Equity Fund, set up with Small Industries Development Bank of India.

(Physical Targets)

FERTILISERS

- 129.99 lakh MT of Nitrogenous Fertiliser production targeted.
- 47.89 lakh MT of Phosphatic Fertiliser production targeted.

COAL AND LIGNITE

- 609.55 million tones of domestic production of Coal has been assessed during 2013-14, which is projected to be met from Coal India Limited and others.
- 26.03 million tones of Lignite production estimated.

STEEL

- 26.00 million tonnes of Iron ore production targeted by National Mineral Development Corporation Ltd.
- 17.41 million tones of saleable steel production by Steel Authority of India Ltd. and Rashtriya Ispat Nigam Ltd. targeted.

NEW AND RENEWABLE ENERGY

- 3000 MW Grid-interactive Power capacity addition from wind, small hydro, biomass power/cogeneration, urban and industrial waste to energy and solar power.
- 1.00 lakh - construction of family type Biogas plants.

RAILWAYS

- 3000 kilometres of track renewal.
- 1300 kilometres of route electrification.
- 750 kilometres of Doubling and manufacturing of additional 675 locomotives.
- 500 kilometres of new lines.
- 450 kilometres of gauge conversion.